International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN:2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 03(II), July-September, 2026, pp. 84-89

राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जाति एवं मतदान व्यवहारः 1998–2023 का विश्लेषण

जय प्रकाश साण्डेला[1*] | डॉ. सुलोचना[2]

[1]शोधार्थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, राजस्थान।
[2]शोध निर्देशक एवं सहायक आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय महाविद्यालय, सीकर, राजस्थान।

[*]Corresponding Author: jaiprakash160197@gmail.com

Citation: साण्डेला, जय एवं सुलोचना (2026). राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जाति एवं मतदान व्यवहारः 1998–2023 का विश्लेषण. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(03(II)), 84–89. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.3(II).9387

सार

वर्तमान शोध आलेख राजस्थान राज्य में राजनीतिक भागीदारी और मतदान व्यवहार की प्रवृत्तियों का जातिगत आयामों एवं बदलते सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में विश्लेषण करता है। 2013, 2018 तथा 2023 के विधानसभा चुनावों के आधिकारिक आंकड़ों, निर्वाचन आयोग के आंकड़ों, जनगणना 2011 एवं विभिन्न विश्वसनीय सर्वे–आधारित रिपोर्टों के आधार पर यह अध्ययन यह दर्शाता है कि राजस्थान में द्विदलीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति के बीच जातिगत तालमेल, कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिकरण, महिला मतदाताओं की बढ़ती सक्रियता तथा नेतृत्व के चरित्र ने मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित किया है। विशेष रूप से महिला मतदान प्रतिशत में पुरुषों की तुलना में बढ़ती भागीदारी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसमें लिंग अंतर लगभग समाप्त हो चुका है। यह आलेख निष्कर्ष निकालता है कि राजस्थान के मतदान व्यवहार में जातिगत आस्था अब भी प्रासंगिक है, किंतु उसका स्वरूप वर्ग, कल्याण एवं व्यक्तिगत लाभ जैसे आधुनिक कारकों के साथ जुड़कर अधिक जटिल एवं बहुआयामी होता जा रहा है।

शब्दकोशः *राजनीतिक भागीदारी, मतदान व्यवहार, जातिगत प्रभाव, महिला मतदाता, राजस्थान चुनाव, कल्याणकारी राजनीति, जातिगत तालमेल, लिंग अंतर।*

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की सफलता का मापदंड मुख्य रूप से नागरिकों की चुनावी भागीदारी एवं उनके मतदान व्यवहार की प्रकृति पर निर्भर करता है। राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल की दृष्टि से), अपनी विशिष्ट सामाजिक–राजनीतिक संरचना एवं द्विदलीय प्रतिस्पर्धा के लिए जाना जाता है, जहाँ पिछले लगभग तीन दशकों से सत्ता परिवर्तन की "घूर्णन–द्वार" (revolving door) प्रवृत्ति देखी गई है अर्थात् शासक दल को सामान्यतः पाँच वर्ष में ही पराजित होना पड़ता है। यह प्रवृत्ति 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जारी रही, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 200 में से 115 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से विस्थापित कर दिया।

इस संदर्भ में यह आलेख यह समझने का प्रयास करता है कि राजस्थान के मतदाता अपना निर्णय कैसे लेते हैं और उनके इस निर्णय को जातिगत संरचना, कल्याणकारी योजनाएँ, नेतृत्व तथा लिंग जैसे कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। 2023 के चुनाव में भाजपा ने 41.69 प्रतिशत वोट शेयर प्राप्त किया, जबकि कांग्रेस का

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

वोट शेयर 39.55 प्रतिशत रहाकृअर्थात् सीटों के अंतर के बावजूद दोनों दलों के वोट शेयर में केवल लगभग 2.2 प्रतिशत का अंतर था। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि राजस्थान में मतदान व्यवहार किसी एक कारक से नहीं, बल्कि अनेक आपस में जुड़े कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है।

शोध पद्धति

वर्तमान अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक शोध प्रकृति का है। इसमें निर्वाचन आयोग के सांख्यिकीय रिपोर्ट, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रकाशित आंकड़े, जनगणना 2011 के आधिकारिक तथ्य, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की विश्लेषण रिपोर्टें तथा प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों एवं शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित सर्वे–आधारित आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

विश्लेषण के लिए 2013, 2018 एवं 2023 के तीन विधानसभा चुनावों को आधार बनाया गया है, ताकि लघुकालिक तथा मध्यकालिक दोनों प्रवृत्तियों की पहचान की जा सके। जातिगत आंकड़ों के संबंध में यह सतर्कता बरती गई है कि जनगणना 2011 में केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आधिकारिक संख्या उपलब्ध हैय शेष जातिगत समूहों के आंकड़े विभिन्न अनुमानों एवं राजस्थान व्ठब् आयोग की हालिया रिपोर्ट पर आधारित हैं, अतः इन्हें अनुमानित माना गया है, न कि आधिकारिक। तालिकाओं एवं चित्रों के माध्यम से आंकड़ों को दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर निष्कर्षों को सुदृढ़ किया गया है।

राजस्थान की सामाजिक–राजनीतिक पृष्ठभूमि

राजस्थान की कुल विधानसभा 200 सदस्यीय है, जिसमें 34 सीटें अनुसूचित जाति एवं 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैंकृअर्थात् कुल 59 (लगभग 30 प्रतिशत) सीटें आरक्षित श्रेणी में आती हैं।

इससे स्पष्ट है कि दलित एवं आदिवासी जनसंख्या राज्य की चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.83 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.48 प्रतिशत है। इनके अतिरिक्त, अन्य पिछड़ा वर्ग समूह जनसंख्या का लगभग 44ृ52 प्रतिशत भाग बनाते हैं, जिनमें जाट सबसे बड़ा एवं राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली समुदाय माना जाता है। राज्य में चार प्रमुख जातीय समूहों जाट, राजपूत, मीणा एवं गुर्जर का चुनावी राजनीति पर विशेष प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त, राज्य की लगभग 9–10 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या भी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे भरतपुर, अलवर एवं नागौर के कुछ हिस्सों) में चुनावी निर्णयों को प्रभावित करती है।

राज्य का भौगोलिक विभाजन भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। मारवाड़ एवं शेखावाटी क्षेत्र जाट बहुल हैं, जहाँ लगभग 31 विधानसभा क्षेत्रों पर इस समुदाय का प्रभाव रहता है। दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्वी राजस्थान (उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर) मीणा एवं भील जनजातीय जनसंख्या का केंद्र है, जबकि पूर्वी राजस्थान (भरतपुर, धौलपुर, करौली) में दलित एवं अन्य समुदायों की सांद्रता चुनावी गणित को निर्धारित करती है। यह भौगोलिक एकाग्रता चुनावी रणनीतियों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है।

राजस्थान की सामाजिक संरचना – प्रमुख समूह

सामाजिक समूह	अनुमानित हिस्सेदार	स्रोत/स्थिति
अनुसूचित जाति	17.83	जनगणना 2011 (आधिकारिक)
अनुसूचित जनजाति	13.48	जनगणना 2011 (आधिकारिक)
अन्य पिछड़ा वर्ग	लगभग 44–52	विविध अनुमान/OBC आयोग
जाट	लगभग 9–12	अनुमानित
राजपूत (सामान्य)	लगभग 6–8	अनुमानित
मीणा	लगभग 6–7	अनुमानित
गुर्जर	लगभग 5–6	अनुमानित
ब्राह्मण (सामान्य)	लगभग 7	अनुमानित
मुस्लिम (अल्पसंख्यक)	लगभग 9–10	जनगणना 2011 (आधिकारिक)

मतदान व्यवहार में जातिगत प्रभाव

राजस्थान के चुनावी राजनीति में जातिगत समीकरण ऐतिहासिक रूप से निर्णायक रहे हैं। जाट समुदाय, जो राज्य की लगभग 9–12 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, पारंपरिक रूप से कांग्रेस के समर्थक माना जाता रहा है, क्योंकि इस समुदाय ने भूमि सुधारों एवं किसान राजनीति में उस पार्टी के साथ सहयोग किया था। इसके विपरीत, राजपूत समुदाय सामान्यतः भाजपा के अनुकूल माना जाता है, विशेषकर वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व काल में। मीणा समुदाय, जो आदिवासी जनसंख्या का सबसे बड़ा खंड है, भी ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के समर्थक रहा है, जबकि गुर्जर समुदाय आरक्षण आंदोलन के बाद से राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय एवं परिवर्तनशील बना है।

तथापि, इस जातिगत विभाजन को यांत्रिक रूप से नहीं देखा जा सकता। विभिन्न चुनावों में यह देखा गया है कि कोई भी समुदाय एकरूप से किसी एक दल के प्रति वफादार नहीं रहता। 2018 के चुनाव में जाट, राजपूत, मीणा एवं गुर्जर समुदायों ने मिश्रित रूप से मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस सत्ता में लौटी। 2023 में यह प्रवृत्ति पुनः बदली और जाट समुदाय का एक बड़ा खंड भाजपा की ओर झुका, जिससे गढ़ लौटने का प्रभाव दृश्य हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि जातिगत वफादारी स्थिर नहीं है, बल्कि शासन–प्रदर्शन, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि एवं स्थानीय मुद्दों के साथ अंतःक्रिया करती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जातिगत तालमेल का है। राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार चुनते हैं, ताकि अधिकतम जातिगत समर्थन जुटाया जा सके। उदाहरण के लिए, भरतपुर क्षेत्र में जाटव एवं माली समुदाय का संतुलन, या दक्षिणी राजस्थान में मीणा एवं गुर्जर आबादी के बीच उम्मीदवारों का चयन, चुनावी रणनीति का केंद्र बनता है। इस प्रकार, जातिगत प्रभाव केवल मतदाताओं के व्यक्तिगत निर्णय तक सीमित नहीं, बल्कि यह दलों की रणनीतिक योजना एवं उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में भी संरचित रूप से निहित है।

गुर्जर समुदाय का मामला जातिगत राजनीति की गतिशील प्रकृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2006–2008 के बीच हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलनों ने इस समुदाय को राजनीतिक रूप से अत्यधिक सक्रिय एवं संगठित कर दिया। इन आंदोलनों ने न केवल राज्य सरकारों को दबाव में डाला, बल्कि गुर्जर नेतृत्व को एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो अपनी माँगों के आधार पर विभिन्न दलों के साथ समझौता कर सकती थी। इसी प्रकार, मीणा समुदाय ने शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है, जिससे दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसका निर्णायक प्रभाव बना रहता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जातिगत पहचान अब केवल एक सामाजिक श्रेणी नहीं, बल्कि संसाधनों, प्रतिनिधित्व एवं सत्ता की राजनीति का एक सक्रिय माध्यम बन चुकी है।

इसके अतिरिक्त, जातिगत पहचान का राजनीतिकरण अब सीधे वोट–बैंक की राजनीति से जुड़ गया है। व्ठब् आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में OBC श्रेणी की 92 जातियों की कुल जनसंख्या लगभग 3.58 करोड़ है, जिसमें जाट (71.76 लाख), गुर्जर (32.68 लाख), कुम्हार–कुमावत (29.97 लाख) एवं माली–सैनी (27.97 लाख) प्रमुख हैं।

ये आंकड़े इस बात को रेखांकित करते हैं कि राजनीतिक दल व्ठब् जनसंख्या के इस बृहत् आधार को संगठित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इस प्रकार, जातिगत प्रभाव एक जटिल एवं गतिशील घटना के रूप में सामने आता है, जो केवल वोट डालने के क्षण तक सीमित नहीं है।

बदलती प्रवृत्तियाँ

- **महिला मतदाताओं की बढ़ती सक्रियता**

राजस्थान के चुनावी परिदृश्य में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी है। 1962 में महिला मतदान प्रतिशत मात्र 41.1 था तथा पुरुषों एवं महिलाओं के बीच लिंग अंतर 21.6 प्रतिशत बिंदु था।

यह अंतर 2023 तक घटकर लगभग 0.2 प्रतिशत बिंदु रह गया है, जब महिला मतदान 74.72 प्रतिशत तथा पुरुष मतदान 74.53 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस दीर्घकालिक परिवर्तन का अर्थ यह है कि अब महिला मतदाता कोई "मौन" या "उप–प्रतिनिधित्व" वाला वर्ग नहीं रहीय वह चुनावी परिणामों को सीधे प्रभावित करने वाला स्वतंत्र राजनीतिक अभिकर्ता (gency) बन चुकी है। विशेष रूप से 2013 एवं 2023 के चुनावों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा (जबकि 2018 में दोनों लगभग समान थे), जो सामाजिक जागरूकता, साक्षरता एवं महिला–केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है।

- **कल्याणकारी राजनीति का राजनीतिकरण**

हाल के चुनावों में कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिकरण एक प्रमुख निर्धारक के रूप में उभरा है। अशोक गहलोत सरकार (2018–2023) ने महिला–केंद्रित एवं कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन, चिकित्सा बीमा, गृहिणी सहायता एवं शिक्षा–संबंधी योजनाओं पर विशेष बल दिया। तथापि, 2023 के चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि केवल कल्याणकारी योजनाएँ ही चुनावी सफलता की गारंटी नहीं हैं। भाजपा ने अपने अभियान को राष्ट्रवादी एवं विकास–केंद्रित विमर्श के साथ जोड़ा तथा प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि को केंद्र में रखा, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस की कल्याणकारी रणनीति कमजोर पड़ गई।

यह इस ओर संकेत करता है कि मतदाता अब "कल्याण के अधिकार" को "राजनीतिक व्यक्तिगत लाभ" के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि शासन–प्रदर्शन एवं समग्र विकास के साथ मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार, कल्याणकारी राजनीति एक आवश्यक, किंतु पर्याप्त न होने वाली शर्त बनकर रह गई है।

- **नेतृत्व, युवा एवं मीडिया का प्रभाव**

नेतृत्व का चरित्र एवं उसकी व्यक्तिगत छवि भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 2023 के चुनाव में भाजपा ने किसी एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार को अग्रभूमि पर रखने के बजाय प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं "डबल इंजन सरकार" के विमर्श पर चुनाव लड़ा, जो सफल सिद्ध हुआ। इसके विपरीत, कांग्रेस के भीतर नेतृत्व का द्वंद्व एवं आंतरिक असंतोष ने उसकी स्थिति कमजोर की। यह इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक चुनावों में नेतृत्व की एकता एवं स्पष्टता निर्णायक होती है।

इसके अतिरिक्त, युवा मतदाता एवं सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव भी एक नया आयाम है। राजस्थान में शहरीकरण, शिक्षा का विस्तार एवं डिजिटल मीडिया की पहुँच ने युवाओं के राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया है। युवा मतदाता पारंपरिक जातिगत वफादारी से अधिक रोजगार, शिक्षा एवं सम्मान जैसे मुद्दों से प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया पर वैचारिक प्रचार एवं नारे चुनावी विमर्श को आकार देते हैं, जिससे मतदान व्यवहार अधिक तेजी से बदलता है। इस प्रकार, पारंपरिक कारकों (जाति, वर्ग) के साथ–साथ आधुनिक कारक (मीडिया, युवा चेतना, नेतृत्व) मिलकर एक बहुस्तरीय निर्णय–प्रक्रिया का निर्माण करते हैं।

- **प्रति–अवस्था एवं क्षेत्रीय विविधता**

राजस्थान की चुनावी राजनीति की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता "घूर्णन–द्वार" अर्थात् प्रत्येक पाँच वर्ष में सत्ता परिवर्तन की प्रवृत्ति है। 1993 से लेकर 2023 तक लगभग प्रत्येक विधानसभा चुनाव में शासक दल को हार का सामना करना पड़ा है। यह प्रवृत्ति मतदाताओं की प्रति–अवस्था (anti-incumbency) भावना को दर्शाती है, जिसमें वे पिछले पाँच वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर शासक दल को दंड देते हैं। तथापि, 2023 के चुनाव ने यह भी दिखाया कि प्रति–अवस्था स्वतः नहीं उत्पन्न होतीय उसे विपक्ष द्वारा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कांग्रेस ने अपनी कल्याणकारी उपलब्धियों को वोट में परिवर्तित नहीं कर पाई, जबकि भाजपा ने प्रधानमंत्री की छवि एवं "डबल इंजन" के विमर्श के माध्यम से प्रति–अवस्था को अपने पक्ष में मोड़ लिया।

क्षेत्रीय विविधता भी मतदान व्यवहार को आकार देती है। मारवाड़ एवं शेखावाटी के जाट बहुल जिले, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान के दलित बहुल जिले तथा शहरी केंद्रों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर) में मतदान पैटर्न भिन्न–भिन्न होते हैं। शहरी क्षेत्रों में मध्यवर्गीय मतदाता विकास,

सुशासन एवं सुविधाओं के मुद्दों पर अधिक केंद्रित होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई, राशन एवं सामाजिक समरसता जैसे मुद्दे प्राथमिकता प्राप्त करते हैं। इस क्षेत्रीय विविधता के कारण राजनीतिक दलों को एकरूप रणनीति के बजाय क्षेत्र–विशिष्ट संदेश एवं उम्मीदवार चयन करना पड़ता है, जो राजस्थान की चुनावी राजनीति की जटिलता को और बढ़ा देता है।

तालिकाओं एवं चित्रों की व्याख्या

तालिका 1 एवं चित्र 1 तीनों चुनावों में दलों के सीट प्रदर्शन को दर्शाते हैं। 2013 में भाजपा का भारी बहुमत (163 सीटें) 2018 में घटकर 73 रह गया, जबकि कांग्रेस 21 से बढ़कर 100 पर पहुँची। 2023 में पुनः भाजपा 115 सीटों के साथ सत्ता में लौटी। यह उतार–चढ़ाव राजस्थान की "घूर्णन–द्वार" प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रमाण है, जहाँ मतदाता पाँच वर्ष में सत्ता परिवर्तन का विकल्प चुनते हैं। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वोट शेयर में भाजपा एवं कांग्रेस के बीच अंतर बहुत कम है (2023 में केवल 2.2 प्रतिशत), अतः सीटों का बड़ा अंतर मतदान व्यवहार की बजाय वोट विभाजन एवं पहली–पोस्ट–द–पोस्ट प्रणाली का परिणाम है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम (2013–2023)

चुनाव वर्ष	भाजपा सीटें	कांग्रेस सीटें	भाजपा वोट शेयर	कांग्रेस वोट शेयर
2013	163	21	लगभग 45	लगभग 33
2018	73	100	38.77	39.30
2023	115	70	41.69	39.55

तालिका 2 एवं चित्र 2 लिंगवार मतदान प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। तीनों चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत 74–76 के बीच रहा, जो राज्य में राजनीतिक भागीदारी की उच्च स्थिति को दर्शाता है। महिला मतदान प्रतिशत 2013 से लगातार पुरुष मतदान के बराबर या उससे अधिक रहा है, जो लिंग अंतर के संकुचन को दृश्य रूप में स्पष्ट करता है। यह रुझान इस बात का सूचक है कि महिला मतदाता अब केवल परिवार द्वारा निर्देशित मतदाता नहीं, बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक निर्णयकर्ता के रूप में उभरी है।

तालिका 2: राजस्थान में लिंगवार मतदान प्रतिशत (2013–2023)

चुनाव वर्ष	कुल मतदान	महिला	पुरुष	लिंग अंतर (प्रतिशत बिंदु)
2013	75.67	75.44	74.67	0.77
2018	74.71	74.67	74.75	0.08
2023	75.45	74.72	74.53	0.19

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजस्थान का मतदान व्यवहार एक बहुआयामी एवं गतिशील घटना है। जातिगत प्रभाव अब भी प्रासंगिक है, किंतु उसका स्वरूप पारंपरिक एकरूपता से मुक्त होकर अधिक जटिल हो चुका है। जातिगत वफादारी अब वर्ग, कल्याण, नेतृत्व एवं व्यक्तिगत लाभ जैसे आधुनिक कारकों के साथ अंतःक्रिया करती है। राज्य की "घूर्णन–द्वार" प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि मतदाता पाँच वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर सत्ता परिवर्तन का विकल्प चुनते हैं, अर्थात् वे किसी एक दल के प्रति स्थायी वफादारी नहीं रखते।

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन महिला मतदाताओं की बढ़ती सक्रियता एवं लिंग अंतर के संकुचन में दिखाई देता है। 1962 से 2023 तक की यात्रा में महिला मतदान 41.1 प्रतिशत से बढ़कर 74.72 प्रतिशत तक पहुँचा है, जो सामाजिक जागरूकता, शिक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक परिणाम है। इसके अतिरिक्त, युवा चेतना, सोशल मीडिया एवं नेतृत्व की व्यक्तिगत छवि ने मतदान व्यवहार को अधिक तेजी से बदलने वाले कारकों में बदल दिया है।

इन निष्कर्षों के आलोक में यह सुझाव दिया जा सकता है कि राजनीतिक दलों को अब केवल जातिगत तालमेल की रणनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि शासन–प्रदर्शन, महिला एवं युवा मुद्दों तथा समावेशी विकास के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निर्वाचन आयोग एवं नागरिक समाज को महिला एवं युवा मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को और सुदृढ़ करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। अंततः, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि मतदाता जातिगत एवं क्षेत्रीय विभाजनों से ऊपर उठकर विकास, समानता एवं न्याय के मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय लें यही राजस्थान के चुनावी अनुभव से निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।

समग्र रूप में, राजस्थान का चुनावी अनुभव यह दर्शाता है कि एक बहुजातीय एवं बहुक्षेत्रीय राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस प्रकार सामाजिक जटिलताओं के बीच अपना मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ का मतदाता न तो पूर्णतः पारंपरिक है और न ही पूर्णतः आधुनिकय वह दोनों के मेल का प्रतिनिधि है। जातिगत पहचान अभी भी चुनावी गणित का एक आयाम बनी हुई है, किंतु महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, युवा चेतना का विस्तार एवं शासन–प्रदर्शन के प्रति संवेदनशीलता यह संकेत देते हैं कि राजस्थान का लोकतंत्र एक अधिक परिपक्व एवं सहभागितामूलक दिशा की ओर अग्रसर है। भविष्य के चुनावों में यह प्रवृत्ति और सुदृढ़ होने की संभावना है, जिससे राज्य की राजनीतिक संस्कृति अधिक समावेशी एवं प्रतिनिधित्वात्मक बनेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. निर्वाचन आयोग भारत, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 सांख्यिकीय रिपोर्ट।
2. India Today, “Congress lost Rajasthan but not by much in vote share”] 4 fnlacj 2023A https://www.indiatoday.in/elections/rajasthan-assembly-polls-2023/story/congress-lost-rajasthan-large-vote-share-bjp-had-higher-margins-election-results-2471786-2023-12&04.
3. Frontline (The Hindu), “Desert state goes back to BJP”, 2023A https://frontline-thehindu-com/politics/rajasthan-assembly-election-2023-desert-state-goes-back-to-bjp/article67618878-ece.
4. Times of India, “More women than men voted in Rajasthan”] uoacj 2023A https://timesofindia-indiatimes-com/city/jaipur/more-women-than-men-voted-rajasthan/articleshow/105523117-cms.
5. India Today (DIU), “Women voters in Rajasthan assembly elections”, 2023A https://www-indiatoday-in/diu/story/rajasthan-assembly-elections-women-voters-ashok-gehlot-congress-bjp-2468233-2023-11-27.
6. अमर उजला, ″74.72ः महिलाओं ने मतदान कर चुनी सरकार″, 27 नवंबर 2023। https://www-amarujala-com/rajasthan/rajasthan-election-2023-74-72-women-cast-votes-empowering-women-s-voting-participation-in-assembly-election-2023-11-27.
7. Business Standard, “Caste calculations in Rajasthan”, 4 twu 2023A https://www-business-standard-com/politics/caste-calculations-in-rajasthan-and-why-pilot-matters-in-30-seats-123060400306_1-html.
8. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), राजस्थान 2023 वोट शेयर विश्लेषण। https://adrindia.org/sites/default/files/Analysis_of_Vote_Share_and_Margin_of_Victory_and_Representativeness_of_Winners_Rajasthan_Assembly_2023_Finalver_English-pdf.
9. News18, “Women voters continue to surpass men in turnout in Rajasthan”] 2023A https://www-news18-com/elections/women-voters-continue-to-surpass-men-in-turnout-in-rajasthan-elections-news18-analysis-8679715-html.
10. जनगणना 2011, राज्य राजस्थान (विकिपीडिया संकलन)।

❑❑❑